

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोशल मीडिया को वनियमित करने का आह्वान

प्रलिस के लिये: [भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सोशल मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, IT अधिनियम, 2000 की धारा 69A, IT अधिनियम, 2000 की धारा 79\(1\), सूचना प्रौद्योगिकी \(मध्यवर्ती दशानरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहिता\) नयिम, 2021, के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ \(2017\), अनुच्छेद 21।](#)

मेन्स के लिये: भारत में सोशल मीडिया का वनियमन, समाज के वभिन्न वर्गों पर सोशल मीडिया का प्रभाव।

[स्रोत: द हद्दि](#)

चर्चा में क्यों?

[सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने हास्य कलाकारों द्वारा की गई आपतजनक टपिपणियों के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए यह टपिपणी की कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभवियक्ता की स्वतंत्रता का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। न्यायालय ने चेतावनी दी कि इस प्रकार की सामग्री कमज़ोर वर्गों की गरमा को ठेस पहुँचा सकती है और सरकार से आग्रह किया कि वह अभवियक्ता की स्वतंत्रता तथा सामाजिक संवेदनशीलताओं के बीच संतुलन स्थापति करने हेतु प्रभावी दशानरिदेश तैयार करे।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख अवलोकन और सफिरशैं

■ प्रमुख अवलोकन:

- **व्यावसायीकरण और जवाबदेही:** सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभवियक्ता की स्वतंत्रता का मुद्रीकरण (Monetisation) करते हैं, जो प्रायः प्रतबिंधति अभवियक्ता के साथ मशिरति हो जाती है। न्यायालय ने चेतावनी दी कि इस प्रकार की अभवियक्ता का उपयोग कमज़ोर वर्गों (दवियांगजन, महिलाएँ, बच्चे, अल्पसंख्यक, वरषिठ नागरकि) पर प्रहार करने के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
- **हास्य बनाम गरमा:** जहाँ हास्य आवश्यक है, वहीं आपतजनक चुटकुले एवं असंवेदनशील टपिपणियाँ कलंक और भेदभाव को बढ़ावा देती हैं तथा वंचति वर्गों को मुख्यधारा में लाने के संवेधानकि दायतिव को ठेस पहुँचाती हैं।
- **डजिटल कषेत्र में स्पष्ट सीमाएँ:** न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अभवियक्ता की स्वतंत्रता, व्यावसायिक अभवियक्ता और प्रतबिंधति अभवियक्ता के बीच स्पष्ट सीमांकन होना चाहिये, क्योंकि गैर-ज़मिमेदार ऑनलाइन टपिपणियाँ गरमा, सामाजिक सद्भाव तथा सामुदायिक वशिवास को कमज़ोर करती हैं।

■ सफिरशैं:

- **परणिामों सहति दशानरिदेश:** केंद्र सरकार को (नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड डजिटल एसोसिएशन से परामर्श कर) इन्फ्लुएंसर/पॉडकास्टर्स के लिये नयिामक दशानरिदेश बनाने का नरिदेश दिया गया, जनिमें अनुपातिक और लागू किये जाने वाले परणिाम हों, केवल 'औपचारकिता' न हो।
- **संवेदनशीलता और ज़मिमेदारी:** सामाजिक नुकसान के लिये उल्लंघनकरत्ताओं की जवाबदेही सुनशिचति करते हुए सोशल मीडिया उपयोगकरत्ताओं के बीच जागरूकता, संवेदनशीलता और डजिटल नैतिकता के महत्त्व पर बल दिया गया।
- **माफी और अधिकारों का संतुलन:** इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्लेटफारमों के माध्यम से बनिा शर्त माफी मांगने का आदेश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य अभवियक्ता की स्वतंत्रता को सीमति करना नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता और गरमा के बीच संतुलन बनाना है ताकि विविधि समाज में सामुदायिक अधिकारों की रक्षा की जा सके।

भारत में सोशल मीडिया के उपयोग को नयितरति करने वाले प्रमुख नयिम क्या हैं?

■ प्रमुख कानून:

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** इलेक्ट्रॉनिक संचार और सोशल मीडिया को नयित्तरति करने वाला प्रमुख कानून है।
 - धारा 79(1) मध्यस्थों (जैसे फेसबुक, X, इंस्टाग्राम) को तृतीय-पक्ष सामग्री के लिये देयता से 'सुरक्षित आश्रय' (Safe harbour) का संरक्षण प्रदान करती है, बशर्ते वे नषिपक्ष मंच के रूप में कार्य करें और सामग्री को नयित्तरति या संशोधित न करें।
 - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A सरकार को संप्रभुता, सुरक्षा, रक्षा, विदेशी संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करने और अपराधों को भड़काने से रोकने के लिये ऑनलाइन सामग्री को अवरोध करने की अनुमति प्रदान करती है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दशा-नरिदेश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने, गैरकानूनी सामग्री को हटाने और गोपनीयता, कॉपीराइट, मानहानि और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का आदेश प्रदान करता है।
 - इन नियमों में 2023 के संशोधन ने मध्यस्थों को भारत सरकार से संबंधित झूठी या भ्रामक सामग्री हटाने के लिये बाध्य किया था। हालाँकि, इसके प्रवर्तन पर सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने दुरुपयोग की आशंका का हवाला देते हुए रोक लगा दी है।
- **प्रमुख न्यायिक घोषणाएँ:**
 - **श्रेया सहिल बनाम भारत संघ (2015)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66A को उसकी अस्पष्टता के कारण नरिस्त कर दिया। न्यायालय ने दोहराया कि आलोचना, व्यंग्य और असहमति अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित हैं, जब तक कि वे अनुच्छेद 19(2) के तहत लगाए गए युक्तिसंगत प्रतिबंधों के दायरे में न आते हों।
 - धारा 66A में कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से झूठी या आपतजनक जानकारी भेजने को अपराध घोषित किया गया था, जिसके लिये अधिकतम 3 वर्ष का कारावास नरिधारित था।
 - **के.एस. पुट्टसवामी बनाम भारत संघ (2017)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की।
 - इस फैसले ने बाद के डेटा संरक्षण उपायों को आकार दिया, जिनमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 शामिल है तथा इसने व्हाट्सएप की गोपनीयता नीतियों तथा आधार डेटा मानकों के नियमन को भी प्रभावित किया।

सोशल मीडिया को वनियमति करने की आवश्यकता क्यों है?

- **कमजोर समूहों की सुरक्षा:** अनियमति प्लेटफॉर्म अपमानजनक सामग्री, साइबर बुल्लगि, ट्रोलगि और शोषण को बढ़ावा देते हैं, खासकर महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, अल्पसंख्यकों और वकिलांग व्यक्तियों के लिये।
- **गलत सूचना और अभद्र भाषा पर अंकुश लगाना:** फर्जी खबरों, डीपफेक, घृणा अभियानों और अतविदी प्रचार का तेजी से प्रसार सामाजिक सद्भाव, लोकतांत्रिक संवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करता है।
 - प्रभावी वनियमन से दुष्प्रचार पारस्थितिकी तंत्र पर अंकुश लगाया जा सकता है तथा सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों की सुरक्षा:** अंतहीन स्क्रॉलिंग, छूट जाने का डर (FOMO) और चुनदा पहचान जैसी वशिषताएँ युवाओं में नशे की लत, चिंता और अवसाद को बढ़ावा देती हैं।
 - वनियमन डिजिटल कल्याण, ज़मिमेदार डिज़ाइन और नैतिक संचार मानकों को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **प्रभावशालियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना:** इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बढ़ते चलन के साथ, उपयोगकर्ता अक्सर अप्रकटित पेड प्रमोशनस और अवैध उत्पादों (जैसे, बेटिंग ऐप्स) के कारण वित्तीय जोखिमों में फंस जाते हैं। वनियमन पारदर्शिता, खुलासा मानदंडों और उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करता है।
- **डेटा गोपनीयता एवं सुरक्षा:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ताओं का डेटा एकत्रित करते हैं, अक्सर उनकी सूचित सहमति के बिना। इससे गोपनीयता का उल्लंघन, नगरानी और लाभ या राजनीतिक प्रभाव के लिये दुरुपयोग होता है। इनका वनियमन, अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त गोपनीयता के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिये आवश्यक है।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ज़मिमेदारी में संतुलन:** अनुच्छेद 19(1)(a) मुक्त अभिव्यक्ति की गारंटी प्रदान करता है, लेकिन यह अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्तिसंगत प्रतिबंधों (लोक व्यवस्था, नैतिकता, शष्टिता, राज्य की सुरक्षा) के अधीन है। वनियमन वैध मुक्त अभिव्यक्ति और हानिकारक/अपमानजनक सामग्री के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है।

भारत में सोशल मीडिया को वनियमति करने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **नियामक क्षमता पर दबाव:** ऑनलाइन सामग्री की अत्यधिक मात्रा के कारण नरितर नगरानी करना कठिन हो जाता है। इसके साथ ही उपयोगकर्ताओं की गुमनामी उन्हें घृणा फैलाने वाले भाषण, फेक न्यूज़ और हानिकारक सामग्री साझा करने के लिये और अधिक साहसी बना देती है, जिससे नियामक क्षमता पर दबाव पड़ता है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नरिणय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होती तथा सामग्री की नगरानी से जुड़ी नीतियों में जवाबदेही का अभाव होता है। स्वतंत्र नगरानी के न होने से इनकी अपारदर्शी कार्यप्रणाली एवं मनमानी फैसलों को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **हानिकारक सामग्री की परभाषा:** हानिकारक सामग्री को परभाषित करना एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों में अंतर के कारण आम सहमति बनाना कठिन हो जाता है। यह अस्पष्टता वैध अभिव्यक्ति तथा प्रतिबंधित भाषण के बीच एक 'ग्रे ज़ोन' (अनश्चित क्षेत्र) उत्पन्न करती है।

- स्वतंत्र अभिव्यक्ति बनाम सेंसरशिप: किसी भी प्रकार का नयिमन प्रयास सेंसरशिप या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश के रूप में देखा जा सकता है, विशेष रूप से तब जब मानदंड स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ और अनुपातिक न हों।
- सीमा पार क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे: हानिकारक सामग्री का एक बड़ा हिस्सा भारत के क्षेत्राधिकार के बाहर से आता है, जिससे घरेलू कानून के तहत प्रवर्तन और वनियमन कठिन हो जाता है।
- राजनीतिक नष्पकषता संबंधी चिंताएँ: सामग्री की नगिरानी से जुड़े नरिणयों पर अकसर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म की नष्पकषता पर सवाल उठते हैं और नयिमक तंत्र में जनता का विश्वास कमजोर पड़ता है।

भारत में सोशल मीडिया की विश्वसनीयता और उपयोगिता में सुधार हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- मज़बूत कानूनी-नीति ढाँचा: IT अधिनयिम, 2000 को डजिटल इंडिया एक्ट के माध्यम से अद्यतन किया जाए, ताकि प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, डेटा सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही किसी भी अतिरिक्त से बचने के लिये न्यायिक नगिरानी का प्रावधान भी आवश्यक है।
- एल्गोरदिमिक पारदर्शिता और जवाबदेही: एल्गोरदिम की ऑडिटिंग, पारदर्शिता रिपोर्ट तथा स्वतंत्र नरीक्षण नकियायों को अनविरय किया जाए। तटस्थता और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिये AI-आधारित मॉडरेशन टूल्स के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- प्रौद्योगिकीय और संस्थागत कषमता: साइबर फॉरेंसिक लैब्स का वसितार किया जाए, एजेंसियों की कषमताओं को सशक्त बनाया जाए तथा गोपनीयता व एन्क्रिप्शन मानकों की रक्षा करते हुए AI-सकषम नगिरानी प्रणालियों का एकीकरण किया जाए।
- डजिटल साकषरता और नैतिक उपयोग: राष्ट्रव्यापी डजिटल साकषरता अभियान चलाए जाएँ, जनिका उद्देश्य गलत सूचना, डीपफेक तथा साइबरबुलगी के खलिफ जागरूकता फैलाना हो। साथ ही ज़मिमेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए एवं ऐसे नैतिक डजिाइन प्रथाओं को अपनाया जाए जो उपयोगकर्त्ता के कल्याण को प्राथमकता दें।
- वैश्विक और बहु-हतिधारक सहयोग: सीमापार वनियमन (Cross-Border Regulation) के लिये अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत किया जाए तथा एक समावेशी व भवषिय-उन्मुख डजिटल पारस्थितिकी तंत्र के नरिमाण हेतु नागरिक समाज, शकिषावर्दों एवं उद्योग जगत की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

नष्पकष

सोशल मीडिया का नयिमन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर समूहों की गरमि और अधिकारों के साथ संतुलित करने के लिये आवश्यक है। मज़बूत कानूनी ढाँचे, प्रौद्योगिकीय समाधान, डजिटल साकषरता तथा नैतिक प्रथाओं के संयोजन से जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है, गलत सूचना को रोका जा सकता है, एवं एक सुरकषति, समावेशी व विश्वसनीय ऑनलाइन पारस्थितिकी तंत्र का नरिमाण किया जा सकता है।

संक्षेप में:

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता संबंधी चिंताओं और जवाबदेही की आवश्यकता के बीच संतुलन को ध्यान में रखते हुए, भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वनियमित करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा के पछिले वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न:

प्रश्न. 'सामाजिक संजाल स्थल' क्या होती हैं और इन स्थलों के क्या सुरकषा उलझने प्रस्तुत होती हैं? (2013)

प्रश्न. बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिये। (2023)